

सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 15.06.2011 को अपराह्न 4:30 बजे हैल्थ स्मार्ट कार्ड (यू-हैल्थ) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

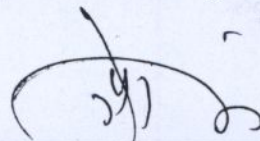
सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.06.2011 को अपराह्न 04:30 बजे हैल्थ स्मार्ट कार्ड (यू-हैल्थ) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थिति थे :-

1. श्री पीयूष सिंह, अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन ।
2. श्री अजय प्रद्योत, अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन ।
3. श्री ओमकार सिंह, अनुसचिव, चिकित्सा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन ।
4. श्री सी.एल. आर्या, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून ।
5. श्री आनेल शाह, अपर निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, देहरादून ।
6. श्री महेश कुमार पन्त, ए.ए.ओ., स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून ।
7. डा. सरोज नैथानी, राज्य नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून ।
8. डा. अतुल अरोड़ा, M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd., पूणे ।
9. श्री सुदीप कुमार वर्मा, M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd., पूणे

- हैल्थ स्मार्ट कार्ड (यू-हैल्थ) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक में विचार-विमर्श हुआ, जिसका विवरण निम्नवत् है :-
- सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा स्मार्ट कार्ड योजना के सम्बन्ध अब तक हुई प्रगति से अवगत करने के निर्देश दिये गये। श्री पीयूष सिंह, अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के द्वारा हैल्थ स्मार्ट कार्ड के सम्बन्ध में अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 2.50 लाख राजकीय कर्मचारी/पेंशनर्स हैं, जिसमें से 5265 राजकीय कर्मिको/ पेंशनर्स द्वारा ही विकल्प पत्र दिया गया है, जिसके सापेक्ष अभी तक 2213 कार्ड ही बनाये जा सके हैं। सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा स्मार्ट कार्ड योजना के सम्बन्ध में अब तक की प्रगति को देखते हुए इस दिशा में और अधिक प्रयास करने पर बल दिया।
- डा० सरोज नैथानी, राज्य नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ के द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में की गयी कार्यशालाओं में राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स द्वारा योजना के सम्बन्ध में कुछ संशोधन किये जाने की अपेक्षा की गई है। राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स द्वारा लगातार यह अनुरोध किया जा रहा है कि रेफरल सिस्टम हटाया जाय, जिससे सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में स्वेच्छा से जाने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके। राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स द्वारा यह मत व्यक्त किया जा रहा है कि स्मार्ट कार्ड योजना के अन्तर्गत

उनके द्वारा अंशदान भी दिया जा रहा है। अतः कार्डधारक को किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

- सचिव, चिकि० एवं स्वा० द्वारा इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये गये, कि शासन द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ किये गये अनुबंध के बिन्दु संख्या-4 में सम्भवतः रेफरल की व्यवस्था को इस आशय से रखा गया था कि रेफरल की व्यवस्था होने से राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स द्वारा स्मार्ट कार्ड का मिथ्या उपयोग नहीं किया जा सकेगा, साथ ही सरकारी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध होने पर भी कार्मिकों द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में इसका लाभ लिये जाने से सरकार पर अनावश्यक रूप से पड़ने वाले वित्तीय व्यय भार से भी बचा जा सकेगा। यद्यपि स्मार्ट कार्ड योजना का उद्देश्य लोगों को अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध कराना है। अतः रेफरल की व्यवस्था हटाने से होने वाली फ्राड/अनियमिताओं से बचाव को देखा जाना होगा।
- बैठक में नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ एवं अनु सचिव, चिकि० एवं स्वा० द्वारा इस सम्बन्ध में सचिव, चिकि० एवं स्वा० का ध्यान आकृष्ट किया गया कि रेफरल सिस्टम होने से राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स योजना के प्रति रूचि प्रकट नहीं कर रहे हैं। अतः कुछ प्रतिबन्धों के साथ रेफरल सिस्टम को रखा जा सकता है या फिर रेफरल की व्यवस्था हटाने से होने वाले फ्राड/अनियमिताओं को रोकने हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किये जा सकते हैं। बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त यह मत निर्णय लिया गया कि रेफरल सिस्टम के सम्बन्ध में यह व्यवस्था निर्धारित कर ली जाय कि कुछ बीमारियाँ यथा:-हृदय, कैंसर, गुर्दा रोग आदि के लिये रेफरल की आवश्यकता की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाय तथा कुछ सामान्य बीमारियों के लिये रेफरल की व्यवस्था निर्धारित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये जायें। इस सन्दर्भ में श्रेणी 'ए' और 'बी' बनाकर बीमारियों का निर्धारण किया जा सकता है। श्रेणी 'ए' में ऐसी बीमारियाँ जिसके लिये रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी तथा श्रेणी 'बी' में ऐसी बीमारियाँ जिसके लिये रेफरल की व्यवस्था आवश्यक होगी। उक्त के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को आपस में समन्वय करके उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
- बैठक में अपर सचिव, चिकित्सा द्वारा सचिव, चिकि० एवं स्वा० को यह भी अवगत कराया गया कि शासन एवं कार्यदायी संस्था के साथ हुए अनुबंध के बिन्दु संख्या-2 (v) में व्यवस्था है कि "Free supply of necessary drugs for out patient prescribe by authorized medical attendant।" बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि स्मार्ट कार्ड धारक एवं उसके आश्रितों के अस्पताल में भर्ती होने की दशा में ही उक्त योजना का लाभ अनुमन्य होगा। वाह्य रोगी के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं समय-समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार व्यवस्था पूर्व की भाँति अनुमन्य होगी। उपरोक्त



दोनों व्यवस्थाएँ साथ-साथ होने की स्थिति में अनुबन्ध के उपरोक्त बिन्दु को वित्त विभाग के परामर्श के बाद संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में अपर सचिव द्वारा वित्त विभाग से भी विचार-विमर्श किये जाने की आवश्यकता व्यक्त की गयी। महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नोडल अधिकारी, यू-हेल्थ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय एवं कार्यदायी संस्था **M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd.**, पूणे को आपस में समन्वय करके उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

- कार्यदायी संस्था **M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd.**, पूणे द्वारा सचिव, चिकि० एवं स्वा० को अवगत कराया गया कि सूचीबद्ध अस्पताल सी.जी.एच.एस. के रेट पर चिकित्सा उपचार का भुगतान किये जाने पर सहमत हुए हैं। अतः उनके साथ चिकित्सा उपचार का भुगतान सी.जी.एच.एस. की दरों पर किये जाने का एम.ओ.यू. किया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सी.जी.एच.एस. में डिस्चार्ज होने के उपरान्त 05 दिन की दवाईयाँ दिये जाने का प्राविधान नहीं है। शासन के साथ हुए अनुबन्ध के बिन्दु संख्या-2 (VI) में चिकित्सा उपचार की समाप्ति के उपरान्त 05 दिन की मुफ्त दवाईयाँ दिये जाने की बाध्यता है। अतः इसे संशोधन किये जाने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया परन्तु सचिव द्वारा अनुबन्ध में दी गयी व्यवस्था अनुसार ही सूचीबद्ध अस्पतालों को 05 दिन की दवाईयाँ रोगी को दिये जाने पर सहमत कराने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिये गये।
- नोडल अधिकारी, यू-हेल्थ द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में उपलब्ध कराये गये विकल्प पत्र में कतिपय त्रुटियाँ थी, जिसे दूर कर अब नये विकल्प पत्र का प्रारूप शासन को भेज कर अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है तथा वर्तमान में इसी विकल्प पत्र के आधार पर कार्मिकों/पेंशनर्स से विकल्प प्राप्त किये जा रहे हैं। अपर सचिव, चिकि० एवं स्वा० द्वारा सचिव चिकि० एवं स्वा० को अवगत कराया गया कि यद्यपि पत्रावली पर संशोधित विकल्प-पत्र के प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त हो गया है तथापि निर्गत नहीं किया गया है। सचिव, चिकि० एवं स्वा० द्वारा विकल्प पत्र में यह भी उपबन्ध डालने के निर्देश दिये कि विकल्प पत्र में व्यक्ति को अपने आश्रितों के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट किया जाना होगा कि परिवार के कौन से सदस्य उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर निवास कर रहे हैं एवं कौन से सदस्य उत्तराखण्ड राज्य के बाहर निवास कर रहे हैं, ताकि कर्मचारी एवं पेंशनर्स के परिवार के सदस्यों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों एवं प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिकों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके तथा यह भी उल्लेख कर दिया जाय कि यदि स्मार्ट कार्ड का मिथ्या उपयोग किसी राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स द्वारा किया जायेगा तो उसकी रिकवरी की जायेगी तथा दोष सिद्ध होने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी। बैठक में सभी बिन्दुओं का समावेश करते हुये पूर्ण परिपक्व विकल्प पत्र का प्रारूप तीन दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराने के

27

निर्देश महानिदेशक, चिकि० एवं स्वा०, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ, उत्तराखण्ड को दिये गये।

- अपर सचिव, चिकि० एवं स्वा० द्वारा सचिव, चिकि. एवं स्वा. को अवगत कराया गया कि वर्तमान में राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं स्मार्ट कार्ड योजना की व्यवस्था दोनों समानान्तर चल रही है तथा ऐसी दशा में किसी व्यक्ति द्वारा दोनों सुविधाओं का एक साथ उपयोग किये जाने की सम्भावना हो सकती है। बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसी सम्भावना को रोकने के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति लिये जाने हेतु कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में यह उल्लेख किया जाना अनिवार्य कर दिया जाये कि वह स्मार्ट कार्ड धारक है अथवा नहीं। यदि वह स्मार्ट कार्डधारक होगा, तो भर्ती होने की दशा में सूचीबद्ध अस्तपालों में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले सकता है और इस हेतु उसे किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यद्यपि वाहय चिकित्सा हेतु वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये स्वतन्त्र है।
- बैठक में राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स के अलावा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं मा० मुख्यमंत्रीजी की घोषणा-राजकीय शिक्षकों की भाँति अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी हैल्थ स्मार्ट कार्ड का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श हुआ। सचिव, चिकि० एवं स्वा० द्वारा बैठक में विचार व्यक्त किया गया कि उक्त योजना केवल राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स के लिये ही है, जिसके अन्तर्गत कर्मचारी/पेंशनर्स अपना अंशदान देकर योजना का लाभ ले रहे हैं। योजना की एक प्रक्रिया निर्धारित है और योजना अभी प्रथम चरण में गतिमान है। अतः ऐसी स्थिति में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को हैल्थ स्मार्ट कार्ड का लाभ दिये जाने से योजना का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है तथा योजना के सम्बन्ध में विसंगति भी उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजना का लाभ इनको इस योजना का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है।
- राज्य नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ द्वारा सरकारी महिला कर्मचारी/अधिकारी होने की दशा में आश्रित के रूप में माता-पिता का निर्धारण किये जाने पर विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया गया। **M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd.**, पूणे के अधिकारीगण द्वारा अवगत कराया गया कि सी.जी.एच.एस. में महिला कर्मचारी इस हेतु स्वतन्त्र है कि वह माता-पिता एवं सास-ससुर में से किसी को भी आश्रित के रूप में चुन लें। बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार परीक्षण करते हुये महानिदेशक, चिकि० स्वा० एवं नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ को उक्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
- विचार-विमर्श के समय यह बिन्दु भी सामने आया कि भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों एवं विभिन्न संस्थानों में इलाज करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य है। अनु सचिव, चिकित्सा द्वारा इस

ओर सचिव का ध्यान आकृष्ट किया गया कि एम्स दिल्ली, पी.जी.आई.-लखनऊ एवं पी.जी.आई.-चण्डीगढ़ जैसे चिकित्सालयों में उत्तराखण्ड के अधिकाधिक कार्मिकों/पेशनर्स द्वारा चिकित्सकीय लाभ लिया जा रहा है। ऐसी दशा में स्मार्ट कार्ड की सुविधा इन अस्पतालों में भी उपलब्ध कराने का अनुरोध व्यक्तियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। सचिव द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये कि भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों एवं विभिन्न संस्थानों को सूचीबद्ध करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि स्मार्ट कार्ड धारकों को भी उपरोक्त चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अस्पतालों को चिकित्सा भुगतान सी.जी.एच.एस. की दरों पर ही किया जा सकता है एवं स्मार्ट कार्डधारक को मुफ्त उपचार की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। इस सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय एवं कार्यदायी संस्था **M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd.**, पूणे को आपस में समन्वय करके विस्तृत प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये ताकि वित्त विभाग के परामर्श के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

- नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 19 व्यक्तियों द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड का लाभ लिया जा चुका है। अभी तक सूचीबद्ध अस्पतालों को भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं हो सका है कि उन्हें कॉरपस फण्ड बनाकर, बचत खाता खोलकर अथवा पी.एल.ए. के माध्यम से भुगतान किया जाय। अनु सचिव द्वारा सचिव को अवगत कराया गया कि कॉरपस फण्ड नियमावली एवं पी.एल.ए. के माध्यम से भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दो पृथक-पृथक पत्रावलियां वित्त विभाग को सन्दर्भित की गयी थी। वित्त विभाग द्वारा कॉरपस फण्ड नियमावली के गठन सम्बन्ध में पत्रावली पर कतिपय पृच्छाएँ की गयी हैं। अतः जब तक कॉरपस फण्ड नियमावली के गठन पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक सूचीबद्ध अस्पतालों को चिकित्सा उपचार का भुगतान पी.एल.ए. के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त विषयक पत्रावली पर वित्त विभाग का परामर्श आने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।
- बैठक के अन्त में सचिव द्वारा कार्यदायी संस्था **M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd.**, पूणे को अधिकाधिक अस्पताल सूचीबद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये। अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा स्मार्ट कार्ड योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2010 एवं दिनांक 14.3.2011 को ली गई बैठकों में अन्य बिन्दुओं पर चर्चा के साथ ही रूम रेन्ट का निर्धारण किये जाने, सहरुग्णता के सम्बन्ध में सूचीबद्ध अस्पतालों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान सी.जी.एच.एस. की दरों पर किये जाने, चिकित्सकीय परामर्श सन्दर्भण की दरों का निर्धारण किये जाने तथा एक साथ कई बीमारियों का पता चलने पर उपचार का पैकेज निर्धारण कर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय निर्णय लिये गये थे, जिनसे बैठक में सचिव, चिकि० एवं स्वा० को अवगत कराया गया।

(277)

इस सम्बन्ध में सचिव, चिकि० एवं स्वा० द्वारा निर्देश दिये कि शासन एवं कार्यदायी संस्था के साथ हुए अनुबन्ध में जो भी संशोधन किये जाने हैं, उसका विस्तृत प्रस्ताव महानिदेशक, चि० एवं स्वा० एवं नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ को उपलब्ध करने हेतु निर्देशित कर दिया जाय ताकि उन पर वित्त विभाग से विचार-विमर्श/परामर्श प्राप्त कर लिया जाय।

- सचिव द्वारा स्मार्ट कार्ड योजना के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव वित्त से एक बैठक का अनुरोध कर उनसे बैठक का समय एवं तिथि व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने के निर्देश अनु सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिये।
- बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर सर्वप्रथम वित्त विभाग से विचार-विमर्श/परामर्श प्राप्त कर लिया जाय [तदोपरान्त ही नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
- सचिव चि० एवं स्वा० द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में महानिदेशक, चिकि० एवं स्वा० एवं नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

(डा० उमाकान्त पंवार)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग-04

संख्या:-459A /xxviii-4-2011-107/2010 टी.सी.

देहरादून: दिनांक 24 जून, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, (पी०पी०पी०), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. डा० सरोज नैथानी, संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी, यू-हैल्थ, देहरादून।
7. डा० अतुल अरोड़ा, M/s MD, India Health Care Services (TPA) Private Ltd., पूणे, महाराष्ट्र।
- ✓ 8. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डा० उमाकान्त पंवार)
सचिव।